ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान (हैदराबाद के विशेष सन्दर्भ में)

Contribution of Sardar Patel in Indian National Integration (With Special Reference to Hyderabad)

Paper Submission: 10/10/2021, Date of Acceptance:23/10/2021, Date of Publication: 24/10/2021

मानसिंह मीणा
शोधार्थी
इतिहास विभाग,
कला शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर,
राजस्थान, भारत

15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किन्तु ये स्वतंत्रता हमें क्षत-विक्षत रूप में प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार की कूटनीति के परिणामस्वरूप देश का विभाजन और इन परिस्थितियों से जनित लाखों शरणार्थियों की समस्या और 562 देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय होने न होने जैसी विषय परिस्थितियों ने भारत की एकता और अखण्ड़ता के समक्ष एक प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया।

लौह पुरूष के रूप में विख्यात सरदार पटेल ने इन विपरित परिस्थितियों में अदम्य साहस, धैर्य, एवं कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुये विभाजन से उत्पन्न समस्याओं पर साम, दाम, दण्ड़, भेद की रणनीति के द्वारा व्यावहारिक परिणाम प्रस्तुत कर 562 रियासतों को एकीकृत करके विराट भारतीय गणराज्य की प्राण प्रतिष्ठा कर राष्ट्र के एकता के सूत्र में बांधने का कार्य पूर्ण किया और एकीकृत भारत के शिल्पकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित की।

India got independence on 15 August 1947. But we got this freedom in a mutilated form. The partition of the country as a result of the diplomacy of the British government and the problem of millions of refugees arising out of these circumstances and the subject circumstances like the non-merger of 562 princely states in the Indian Union raised a question mark in front of the unity and integrity of India. Known as the Iron Man, Sardar Patel, while providing indomitable courage, patience, and efficient leadership in these adverse circumstances, gave Sama, price, punishment, By integrating 562 princely states by presenting practical results through the strategy of distinction, completed the task of tying the unity of the nation by consecrating the great Indian Republic and establishing his identity as the architect of a unified India.

मुख्य शब्द एकीकरण, रियासत, अखण्ड़ता, एकीकृत, विभाजन, स्वतंत्रता।
Keywords: Unification, Principality, Integrity, Unified, Partition, Independence

प्रस्तावना

ब्रिटिश शासन के दौरान अविभाजित भारत में नाममात्र के स्वायत राज्य थे। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में 'रियासत', 'रजवाड़े' या व्यापक अर्थ में देशी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश शासन द्वारा सीधे शासित नहीं थे बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे। उन भारतीय शासको पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहता था। सन् 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यहाँ 562 रियासतें थीं। इनमें से अधिकाशं रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोकसेवा प्रदान करने एवं टैक्स वसूलने का ठेका ले लिया था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने पर इन सभी रियासतों को भारत और विभाजन के बाद बने पाकिस्तान में मिला लिया गया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व जूनागढ़, हैदाराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों का विलीनीकरण का कार्य सम्पन्न हो चुका था। इन तीन रियासतों का विलय आजादी के बाद हो पाया।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध प्रबंध में सरदार वल्लभभाई पटेल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किए गए योगदान नेतृत्व और अन्य सुधारात्मक एवं कार्यों तथा भारतके एकीकरण में उनके अतुल्य योगदान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है। अभीतक उनके जीवन के विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य की विपुल संभावनाएँ है।

1. प्रस्तावित कार्य का मुख्य उद्देश्य उपर्युक्त विषय पर व्यवस्थित एवं प्रमाणिक विवेचन प्रस्तुत करना है।
2. सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किये गये कार्यो का क्रमबद्ध अध्ययन करना शोध का मूल उद्देश्य है।
3. सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा विभिन्न आन्दोलनों में किये गये सामाजिक, आर्थिक कार्यों व अंगेजों के अत्याचारों का विरोध करना आदि हमारे शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य है।
4. हमारे शोध कार्य का उद्देश्य यह भी रहेगा कि सरदार पटेल से सम्बन्धित नवीन एवं भौतिक स्त्रोतों से उनके जीवन के अनछुए पक्षों को उजागरकरना।

साहित्यावलोकन

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभभाई पटेल अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनके कार्यों के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों ने उन पर पुस्तकें व लेखन प्रकाशित किये हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है "सरदार वल्लभ भाई पटेल" के नाम से नरहरी पारीक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसमें सरदार पटेल की संपूर्ण जीवनी को प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके प्रारंभिक जीवन बाल्यकाल से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तथा अंतिम समय तक के कार्यों का उल्लेख किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित विवरण डी.वी. तेहमानकर की पुस्तक"सरदार पटेल' में उपलब्ध है।दुर्गादास (एडिटर) के द्वारा सरदार वल्लभ भाई के पत्र व्यवहार के नाम से 1945-50 तक के 10 खण्डों का प्रकाशन किया है। मणिबेन के द्वारा "सरदार श्रीके विशिष्ठ और अनोखे पत्र' 1947-1950 आदि का प्रकाशन किया गया, उनमें पटेल के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है।राजमोहन गांधी के द्वारा "पटेलः ए लाइफ' के नाम से पुस्तक लिखी गयी।जिसमें पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला है और उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में किये कार्यो का वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

इनके अलावा सरदार पटेल के जीवन एवं विभिन्न आन्दोलनों में उनकी भूमिका पर कई अन्य लेखकों के ग्रन्थ प्रकाशित हुए है। जिन्हें सभी लेखकों ने सरदार पटेल के प्रति अपने दृष्टिकोण से लिखा है। हमारे शोध प्रबन्ध में प्रकाशित विभिन्न लेखकों के विभागों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए सबसे पहले प्राथमिक मूल स्त्रोतों से आंकड़ों एवं तथ्यों का एकत्रण व संकलन किया जायेगा। इस हेतु प्रकाशित व अप्रकाशित शोधग्रन्थों, सरकारी गजेटियर्स, पत्र-पत्रिकाओं, उत्तरकालीन ग्रन्थों, समसामयिक एवंपरवर्तीकालीन इतिहास तथा तत्कालीन साहित्यों,सरकारी व गैर सरकारी रिकार्डस आदि आंकड़ों व तथ्यों का चयन एवं विश्लेषण किया जायेगा।तत्पश्चात्सत्य पर आधारित निष्कर्ष निकालें जायेंगे। हमारे शोध कार्य की प्रकृति ऐतिहासिक,विवरणात्मक तथा विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित होगी।

सरदार पटेलः राष्ट्र निर्माता के रूप में

सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखण्ड़ता को बनाये रखने के लिये देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को कांगेस की भावी रणनीति और स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके महत्व को स्पष्ट करते हुये 5 जुलाई 1947 अपने सम्बोधन में कहा था कि-

"कांग्रेस रजवाडों की दुश्मन नही है। वह देशी रियासतों एवं उसकी प्रजा का हित चाहती है। हम सम्मिलित पुरूषार्थ से ही देश को महान बना सकेगे, लेकिन एकता की कमी होगी तो नयी आपत्तियों का मुकाबला करना होगा। आम लोगो के हित के लिये यदि सब का सहयोग नही होगा तो अंधाधुधी फैल जायेगी और वह हम छोटो-बड़ो को तबाह कर देगी। चलिये हम सब एक साथ संगठित रूप से पुरूषार्थ करे और इस पवित्रा भूमि को दुनिया के देशों में योग्य स्थान दिलाकर भारत की शांति एवं समृद्धि की भूमि बना दे।"

सरदार पटेल ने अपने इस सम्बोंधन में देशी रियासतों के सम्बंध में अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया। उन्होनें सभी रियासतों से आपसी सहयोग और समन्वयकारी रूप की अपेक्षा की तथा रियासतों को खुशहाल और समृद्ध भारत की नींव रखने हेतु प्रेरित किया।

रियासती विभाग की स्थापना

5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना सरदार पटेल के अधीन की गई व इनकी सहायता के लिए वी.पी. मेनन को नियुक्त किया गया। ये इन लोगों के द्वारा सभी रियासतों के साथ मैत्री पूर्ण समझोते किये गये।

15 जुलाई 1947 को लार्ड माउण्टबेटन के द्वारा नरेन्द्र-मण्डल को एक बैठक बुलाई गयी। जिसमें लार्ड माउण्ट बेटन ने अपने विचार रखते हुये कहा कि रक्षा सम्बन्धि, विदेशी मामलें व यातायात सम्बन्धित मामले भारत या पाकिस्तान को केन्द्रिय सरकार को दे देगे । यहाँ पर ही एक उपसमिति का गठन किया गया जो रियासतों के साथ होने वाले समयपूर्ण समझौतों का मसवदा तैयार करेगी।

भारत की आजादी के दिन तक 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर को छोडकर सभी रियासतों को सम्मिलित कर लिया गया था इसके पश्चात भी अनेक राजा-महाराजाओं को दिशा भ्रमित करने में मुस्लिम लोग प्रयास कर रही। जिसको लेकर अनेक बार सरदार पटेल, माउण्ट बेटन व वी.पी. मेनन को ही स्थिति के बारे में स्पष्ट किया। इनमें वर्तमान गुजरात, राजस्थान व मध्यप्रदेश को प्रमुख रियासतें थी।

सरदार पटेल और हैदराबाद का विलय

जंग आदि ने वार्ताओं में नवाब की ओर से प्रतिनिधित्व किया।

इसी दौरान निजाम ने पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल मोहम्मद अली जिन्ना से भी सम्पर्क साधने में भी लगा हुआ था साथ ही साथ अपने कुछ विश्वस्त लोगों को जिन्ना से वार्ता हेतु भी भेजा। नवाब आर्थिक रूप से समृद्ध था। इसी आर्थिक स्थिति के बल पर निजाम ने चेकोस्लोवाकिया को पाँच करोड के हथियार खरीदने का भी आदेश दिया था।

अक्टूबर 1947 को एक मसौदा तैयार करवाया जिसमें विलय तथा यथावत् करार व निजाम के हस्ताक्षर वाले पत्र को संलग्न किया। इस प्रकार का मसौदा जब लेकर निजाम का

प्रतिनिधि मण्डल हैदराबाद पहुंचा। 25 अक्टूबर को निजाम की एक्जिक्यूटिव काउन्सिल ने इसे स्वीकार करने की सलाह दी। लेकिन निजाम ने इसे अगले 2 दिन तक टालता रहा। इसी बीच 27 अक्टूबर को काजिम रिजवी के नेतृत्व में राजाकारों ने प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को घेर लिया। ताकि इन सभी सदस्यों को दिल्ली वार्ता हेतु जाने से रोका जा सके। 28 अक्टूबर को रिजवी ने नवाब छतारी, व मोकटन की उपस्थिति में कहा कि भारत सरकार अभी स्वयं की समस्याओं में घिरी हुई है अतः वह हमारा कुछ नही बिगाड सकती।[4]

अतः हमें इस प्रकार के किसी भी मसौदे का स्वीकार नही करना चाहिए। इसी बीच तीनों सदस्यों ने अपना-अपना त्याग पत्र दे दिया। इसी दौरान निजाम ने काजिम रिजवी की सलाह पर अपने प्रधानमंत्री पद पर नवाब छतारी के स्थान पर हैदराबाद के एक व्यापारी मीर लायक अली को नियुक्त किया। जो काजिम रिजवी का समर्थक था।[5]

इसी समय जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के पराक्रम और जूनागढ की कार्यवाही से निजाम ने अपनी कुटनीति में बदलाव करते हुये सकारात्मक रूख अपनाने लगा। अन्ततः 29 नवम्बर 1947 को निजाम ने एक यथास्थिति सन्धि की जो कि 1 वर्ष के लिए थी इसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार थे।

आगामी समझौते तक हैदराबाद के रक्षा, विदेश और संचार के मामले भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र मे होगे। इसी में कहा गया कि भारत सरकार व हैदराबाद आपस में एक दूसरे के पास अपने-अपने एजेन्ट जनरलों को नियुक्त करेगी। भारत सरकार ने अपना एजेन्ट जनरल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को नियुक्त किया था। माउण्ट बैटन भी सरदार पटेल की तरह एकीकरण हेतु कटिबद्ध थे। इन्ही के अनुरोध पर सरदार पटेल ने तीन माह और बढाना तय किया।

इस समझौते का फायदा उठाते हुये निजाम ने अपनी राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक स्थिति को सुदृढ बनाने व स्वतंत्र राष्ट्र के सपने को सजोने में लगा रहा। निजाम ने इस समय दो आदेश जारी कियें जिनमें -सोने, चाँदी को हैदराबाद से बाहर भारत भेजने पर रोक व भारतीय करैंसी को हैदराबाद में अवैध घोषित कर दिया व पाकिस्तान को भारतीय प्रतिभूतियों के रूप मे 20 करोड रूपया का ऋण भी दिया। साथ ही साथ अपना एक अधिकारी करांची में नियुक्त किया। भारत सरकार को वाक् युद्ध के द्वारा उकसाने लगा।[6]

हैदराबाद की फौज के रूप में भर्ती कियें गये रजाकारों का आतंक दिनो-दिन बढने लगा इन्होंने न केवल हैदराबाद अपितु आस-पास के राज्यों में भी लूटपाट, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी विकट स्थिति पैदा कर दी। सभी रजाकारों को नेतृत्व काजिम रिजवी कर रहे थे जो हर नये दिन अलग-अलग बातों के द्वारा आंतक को बढाने में सहयोग देने लगे।

इसी समय समाचार पत्रों में काजिम रिजवी का भाषण प्रकाशित हुआ कि जिसमें मुसलमानों को एक हाथ में कुरान व एक हाथ में तलवार लेकर आगे बढना चाहिए व
भारतीय संघ में 45 मिलियन मुसलमान किसी भी प्रदर्शन में हमारे पांचवे स्तम्भ होगे। इस प्रकार के व्यक्तव्य को लेकर मोंकटन ने भारत सरकार को आश्वस्त किया कि वह वापिस हैदराबाद पहुंचकर निजाम से काजिम रिजवी पर कार्यवाही करने की सलाह देगा।[7]

इस समय काजिम रिजवी रजाकारों की सहायता से चारो और आंतक कर माहौल पैदा करने में लगा हुआ था जब काजिम रिजवी दिल्ली आये उसने सरदार पटेल व वी.पी. मेनन से मुलाकात की जिसमें सरदार पटेल से कहा कि हम अन्तिम दम तक लडेगे। सरदार पटेल ने इसका प्रति उत्तर देते हुये कहा कि "मै तुम्हे आत्महत्या करने से कैसे रोक सकता है।"इसी समय वी.पी. मेनन ने भी काजिम रिजवी के उन्माद व कट्टरता को बहुत करीब से देखा।[8]

जब सरदार पटेल ने दिल्ली में हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लायक अली से मुलाकात की और अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि हम हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए अति उत्साहित नहीं है। हम तो सिर्फ हैदराबाद में शांति स्थापित करने के पक्षधर है जिसमें हिन्दुओं की सुरक्षा व जेलों में बंद प्रजामंडल के नेतृत्व व कार्यकर्ताओं को आजाद करने व हिन्दुओं को निजाम के प्रशासन में उचित स्थान देने की बात करता है।[9] भारत सरकार ने अपनी बात रखते हुये निजाम से कहा कि वे या तो भारत संघ में हैदराबाद के विलय को स्वीकार करे या हैदराबाद में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करे।[10]

भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल का लार्ड माउण्टबेटन का कार्यकाल भी जल्दी ही पूरा होने वाला था। अतः वह निजाम की अच्छी बुरी बातों को भी मानकर समझौते के पक्ष में थे। हैदराबाद के प्रतिनिधि के प्रतिनिधिमण्डल से वार्ता के दौरान "सहमति के मुद्दे" के नाम से एक प्लान तैयार किया गया। इस पर लायक अली ने स्वीकृति दी। लेकिन 30 मई को इसमें सुधार करने हेतु इच्छा प्रकट की। जिसको लार्ड लुई माउण्टबेटन ने स्वीकृति दी।

निजाम के कानूनी सलाहकार वाल्टर मोकटन 12 जून को संशोधित "सहमति के मुद्दे" लेकर दिल्ली पहंुचे। इस मुद्दों पर निजाम की स्वीकृति लेते हुये मोकटन ने कहा कि भारत सरकार का इन विषयों को स्वीकार करना हैदराबाद के लिए चमत्कार के सामान होगा। इन मुद्दो को लेकर मोंकटन, माउण्टबेटन से बात करते है लेकिन उन्होने कहा कि सरदार पटेल कभी भी इन बिन्दुओं पर अपनी सहमति नही देगे। लेकिन मोकटन के द्वारा बार-बार आग्रह करने के बाद माउण्टबेटन

इस विषय पर सरदार पटेल से बात करने हेतु तैयार हो गये है। माउण्ट बेटन अपने साथ जवाहर लाल नेहरू, गोपालस्वामी, राजेन्द्र प्रसाद व बलदेव सिंह के साथ सरदार से मिलने पहुंच गये।

सभी नेताओं को यह विश्वास था कि सरदार पटेल कभी भी इस विषय पर अपनी सहमति नही देगे। सरदार पटेल इस मसौदे में सहमति देते है तो मै इसे लागू करवाने का वचन देता हू।[11] लेकिन जब सरदार पटेल को यह मसौदा दिखाया गया तो वे नाराज हो गये और साफ तोर पर मना कर दिया लेकिन जब लार्ड माउण्टबेटन अन्तिम मुलाकात कहकर विदाई ले रहे थे तब सरदार ने उन्हें उनके कार्यो को लेकर याद करन की बात कही और अन्त में 13 जून 1948 को सरदार पटेल ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिया जिसके बिन्दू निम्न प्रकार है।[12]

1. भारत सरकार के समान ही निजाम को सुरक्षा संचार साधनों और विदेशी मामलों में समान कानून बनाने की स्वीकृति।
2. हैदराबाद की सेना में 20000 से ज्यादा स्थायी सैनिक नही रखे जायेगे व 8000 तक अनियमित ही रह सकेगे। .
3. काजिम रिजवी के द्वारा भर्ती किये गये रजाकारों को सेना से निकाल दिया जायेगा।
4. हैदराबाद के विदेशी सम्बन्धों का संचालन भारत सरकार को देना तय किया गया।
5. सभी राजनैतिक दल व समुदायों से अन्तिरम सरकार का गठन जैसे बिन्दुओं का यह मसौदा तैयार किया गया।

भारत सरकार की सहमति के बाद मीर लायक अली व मोंकटन हैदराबाद गये।[13]जहाँ 17 जून को निजाम व मंत्रिमण्डल से वार्ता के दौरान इस मसौदे पर निजाम ने अपनी स्वीकृति देने से मना कर दिया। इस बार फिर काजिम रिजवी की कुटिल चालों का परिणाम रहा जो निजाम के साम्राज्य को गर्त में की ओर धकेल रहा था।

माउण्ट बेटन की भारत से विदाई के बाद अब सरदार पटेल ने कडा रूख अख्तियार करना प्रारम्भ कर लिया था।[14] सर्वप्रथम सरदार पटेल ने हैदराबाद पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना प्रारम्भ किया।[15]इसी दौरान सैन्य कार्यवाही की भी अनुमति प्राप्त कर ली। कुछ लोगों ने सेना की हैदराबाद में कार्यवाही को गलत ठहराने का प्रयास किया। जिसका जवाब सरदार पटेल ने साफ शब्दों में दिया भारत सरकार की प्रतिष्ठा हैदराबाद पर कार्यवाही करने में है न की निर्थक बातें करने में। इसी बीच हैदराबाद में रजाकारों की उदण्डता दिन प्रतिदिन बढने लगी थी। इसके विपरीत भारत सरकार पर ही सन्धि तोडने का अपराध लगाने लगे। निजाम ने अपना एक दल कराची होते हुये न्यूयार्क भेजा। जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बात रख सके।

लार्ड माउण्ट बेटन के भारत छोडने के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी. राज गोपालाचारी ने 31 अगस्त 1948 को निजाम को पत्र लिख कर हैदराबाद की स्थिति के लिए असन्तोष प्रकट किया। लेकिन निजाम ने जवाब देते हुऐ 5 सितम्बर को पत्र लिखा और कहा कि आप के द्वारा कही गयी बाते असत्य है। सरदार पटेल पूर्णरूप से सैन्य कार्यवाही हेतु तैयार हो गये जिसकी स्वीकृति भी इन्होने प्राप्त कर ली थी।

हैदराबाद के विरूद्व 'ऑपरेशन पोलो'

भारत सरकार के आदेश के अनुपालना करते हुये 13 सितम्बर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में कार्यवाही हेतु कूच किया जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया।[16] सेना का नेतृत्व जनरल जे.एन. चौधरी के द्वारा किया गया। जिसको दो भागों में बाँट कर दो दिशाओं से आक्रमण हुआ। जिसमें मुख्य सेना शोलापुर हैदराबाद के मार्ग से आगे बढी जबकि दूसरी टुकडी बैजवाडा हैदराबाद मार्ग से आगे बढी इसी समय सेना को संघर्ष का सामना करना पडा जिस पर जल्दी ही विजय प्राप्त कर ली गयी।[17]

पाँच दिन की इस कार्यवाही के बाद 17 सितम्बर को हैदराबाद की सेना ने सम्पर्ण कर दिया। जिसमें भारतीय सेना के 42 जवान मारे गये थे। 97 घायल हुये व 24 जवान लापता हो गये थे। इसके विपरीत हैदराबाद की सेना में 490 सैनिक मरे व 122 घायल हुये। रजाकारों की ओर से 2727 मारे गये 102 घायल व 3364 को बंदी बनाया गया। 19 सिंतबर को काजिम रिजवी का गिरफ्तार किया गया। जबकि निजाम को हैदराबाद का वैधानिक शासक मान लिया गया। जनरल जे.एन. चौधरी सैनिक गवर्नर नियुक्त किये गये।[18]

संयुक्त राष्ट्र संघ को जवाब देते हुये कहा गया कि ये एक पुलिस कार्यवाही थी। 22 सितम्बर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने तार से सूचित करते हुये अपने मुकदमे को संयुक्त राष्ट्रसंघ से वापिस ले लिया। 21 नवम्बर को हस्ताक्षर द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कर दिया गया।[1]

निष्कर्ष

सरदार पटेल का दर्शन था 'तेरा वैभव अमर रहे माँ' हम दिन चार रहे न रहे। इस प्रकार हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा पर स्वागत करने से मना करने पर सरदार पटेल ने बस इतनी सी बात निजाम को कही याद रहे ये भारत के प्रधानमंत्री है। इतना सुनते ही अगले दिन निजाम गुलदस्ता लेकर भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत कर्ता की पंक्ति में सबसे आगे थे। सरदार पटेल एक महान कूटनीतिग्य थे। वे सामने वाले को देखते ही समझने का गुण रखते थे। माउण्ट बेटन ने अपनी आत्मकथा में सरदार पटेल हेतु "केजरज डिप्लोमेट' कहा था। सरदार वल्लभ भाई ने प्रसिद्धि, यश, व्यक्तिगत लाभ व पद से मिलों दूर एक मौन साधक की तरह राष्ट्रीय एकीकरण में लगे हुये थे, और राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मेनन, वी.पी., दी स्टोरी ऑफ इन्टीग्रेषन ऑफ दी इण्डियन स्टेट्स, पृ. 217*
2. *गुप्त, विशव प्रकाशव मोहनी गुप्त, सरदार वल्लभभाई पटेलः व्यक्ति और विचार, पृ. 136*
3. *गॉधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, पृ. 476*
4. *मेनन, वी.पी., दी स्टोरी ऑफ इटीग्रेशन ऑफ दी इण्डियन स्टेट्स, पृ. 329*
5. *गुप्त, विशव प्रकाश व मोहनी गुप्त, सरदार वल्लभभाई पटेलः व्यक्ति और विचार, पृ. 136*
6. *मेनन, वी.पी., दी स्टोरी ऑफ इटीग्रेषन ऑफ दी इण्डियन स्टेट्स, पृ. 351*
7. *गॉधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, पृ. 477*
8. *गुप्त, विशव प्रकाश व मोहनी गुप्त, सरदार वल्लभभाई पटेलः व्यक्ति और विचार, पृ. 137*
9. *मेनन, वी.पी., दी स्टोरी ऑफ इटीग्रेषन ऑफ दी इण्डियन स्टेट्स, पृ. 329*
10. *गुप्त, विष्वप्रकाष व मोहनी गुप्त, सरदार वल्लभभाई पटेलः व्यक्ति और विचार, पृ. 137*
11. *गॉधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, पृ. 479*
12. *वही, पृ. 479*
13. *जी. एम. नान्दुरकर (सपा.) सरदार पटेल्स सेन्टिनरी वॉल्यूम-1 में उद्धृत, पृ. 244-45*
14. *गुप्त, विशव प्रकाश व मोहनी गुप्त, सरदार वल्लभभाई पटेलः व्यक्ति और विचार, पृ. 137*
15. *पटेल टू गाडगिल लैटर, 21.06.1948*
16. *गॉधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, पृ. 482*
17. *गुप्त, विष्वप्रकाष व मोहनी गुप्त, सरदार वल्लभभाई पटेलः व्यक्ति और विचार, पृ. 137*
18. *गॉधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, पृ. 483*
19. *कुमार, रविन्द्र, सरदार वल्लभभाई पटेल के सामाजिक व राजनैतिक विचार, 1991, पृ. 307-308*